RNI No. RAJHIN/2001/05699

हैलो सरकार

जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

www.hellosarkar.com

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉन ऑन करें- www.hellosarkar.com

हैलो सरकार समाचार पत्र में नियमित पाठक बनने, समाचार की प्रति मंगवाने व विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें
फोनः 0141-2202717
मोः 9214203182
वाट्सप नं. 9928078717

सुविचार

खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दुःख होता है।

-चाणक्य

वर्ष-25 | अंक-265 | दैनिक प्रभात संस्करण | जयपुर, शुक्रवार 29 मई, 2026 | पृष्ठ-4 | मूल्यः 2.50

अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

पानी-बिजली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं-डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा

हैलो सरकार न्यूज

राजसमंद। उपमुख्यमंत्री एवं राजसमंद प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने गुरुवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पानी और बिजली आपूर्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए और सरकार की हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

बैठक में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, विधायक दीप्ति माहेश्वरी, विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल सहित कई जनप्रतिनिधि

मौजूद रहे। वहीं जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए।

बैठक के दौरान राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, समर कंटीजेंसी प्लान, जल संरक्षण अभियान वंदे गंगा, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और ग्रामीण विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। डॉ. बैरवा ने अधिकारियों को विकास कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने और नियमित मॉनिटरिंग बनाए रखने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी अभियान वंदे गंगा जल संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम है। इसके तहत तालाबों, बावड़ियों और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई, जल संरक्षण संरचनाओं के जीर्णोद्धार, पेयजल टंकियों की सफाई तथा खराब हैंडपंपों की मरम्मत जैसे कार्य मिशन मोड में किए जाएंगे।

बैठक में जनप्रतिनिधियों ने बाधेरी परियोजना से पेयजल सप्लाई, बिजली व्यवस्था, चिकित्सा सेवाओं और फार्म पॉण्ड से जुड़े मुद्दे उठाए। इस पर उपमुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

डॉ. बैरवा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता के साथ काम करने और विकास कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने को कहा।

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, योजना में बदलाव, अब आसान होगा फसल बीमा क्लेम

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब किसानों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने फसल बीमा दावों की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए दिवंगत कृषकों के लंबित क्लेम का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश जारी किए हैं। कृषि विभाग के इस फैसले से हजारों किसान परिवारों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है।

राज्य सरकार लगातार किसान हित में कार्य कर रही है और प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मजबूत बनाया जा रहा है। बदलते मौसम, ओलावृष्टि, चक्रवाती बारिश और कटाई के बाद खेत में रखी फसल खराब होने जैसी परिस्थितियों में यह योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच साबित हो रही है।

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि अब तक फसल बीमा योजना में बीमित किसान की मृत्यु होने पर उसके वारिसों को बीमा राशि प्राप्त करने के लिए न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य था। यह प्रक्रिया काफी जटिल और समय लेने वाली थी। कई मामलों में क्लेम राशि कम होने के कारण किसान परिवार कानूनी प्रक्रिया में रुचि नहीं लेते थे, जिससे हजारों दावे लंबे समय से लंबित पड़े थे।

अब सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल बनाते हुए बीमा कंपनियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। यदि राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसान ने किसी परिवार सदस्य को नामित किया है तो बीमा राशि सीधे उसी सदस्य को दी जाएगी। वहीं जिन मामलों में नामांकन उपलब्ध नहीं है, वहां तहसीलदार या पटवारी द्वारा जारी वारिसनामा, न्यायालय का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अथवा परिवार के सभी सदस्यों की सहमति से अधिकृत किसी एक सदस्य को भुगतान किया जा सकेगा।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जहां पारिवारिक विवाद नहीं है, वहां उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। यदि परिवार के सभी सदस्य 50 रुपए के नोटरी स्टाम्प पर शपथ पत्र देकर किसी एक सदस्य को अधिकृत करते हैं तो बीमा कंपनी सीधे उसके बैंक खाते में क्लेम राशि जमा करेगी।

फसल बीमा क्लेम के लिए अब मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाते की प्रति, आधार कार्ड और पारिवारिक सहमति शपथ पत्र जैसे दस्तावेज ही पर्याप्त माने जाएंगे। कृषि विभाग ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि दिवंगत किसानों के मामलों का मानवीय संवेदनशीलता के साथ प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए ताकि प्रभावित परिवारों को जल्द आर्थिक सहायता मिल सके।

राज्य सरकार की इस पहल को कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने भी सराहा है। माना जा रहा है कि इस फैसले से लंबे समय से लंबित हजारों फसल बीमा दावों का जल्द निस्तारण हो सकेगा और किसान परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

अजमेर से जियारत कर लौट रही बोलेरो का टायर फटा, मां-बेटे समेत 4 की मौत, 3 गंभीर घायल

हैलो सरकार न्यूज, बालोतरा। बाड़मेर-जोधपुर नेशनल हाईवे पर पचपदरा थाना क्षेत्र के भाडियावास गांव के पास गुरुवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अजमेर दरगाह से जियारत कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी का अचानक टायर फट गया। टायर फटते ही गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई और सड़क से करीब 10 फीट नीचे जा गिरी। इस भीषण हादसे में मां-बेटे समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी मृतक और घायल बाड़मेर जिले के चौहटन क्षेत्र के रहने वाले हैं। पचपदरा थाना एएसआई अमराराम के अनुसार, हादसा गुरुवार शाम करीब 4 बजे हुआ। बोलेरो में कुल 8 लोग सवार थे, जो ईद के पावन मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह में जियारत करने गए थे। वहां से वापस अपने गांव कोनरा विलायतशाह (चौहटन) लौटते समय भाडियावास गांव के समीप अचानक चलती गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया। रफ्तार तेज होने के कारण चालक नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी पलटते हुए खाई में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही पचपदरा थाना पुलिस तुरंत मौके पर

पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में फंसे घायल 7 लोगों को बाहर निकालकर बालोतरा के नाहटा जिला अस्पताल पहुंचाया।

अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं, दो गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल जोधपुर रेफर किया गया, जिनमें से एक घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अन्य दो घायलों का बालोतरा के ही एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।

हादसे का शिकार हुए लोग - मृतक-रहमत (52) पत्नी नूर मोहम्मद, उनका 8 वर्षीय मासूम बेटा अरशद, कादर खान (35) पुत्र इनायत और हबीब खान (45) (जिसकी जोधपुर में मौत हुई)।

घायल-काजे खां (जोधपुर रेफर), रजाक खान और सवाई खान (बालोतरा में उपचाराधीन)।

परिजनों के आने पर होगा पोस्टमार्टम - पुलिस ने बताया कि दुर्घटना की जानकारी मृतकों और घायलों के परिजनों को दे दी गई है। परिजनों के बालोतरा पहुंचने के बाद शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें सुपुर्द किया जाएगा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

राजस्थान के 33 जिलों को नई सड़कों की सौगात

सीएम भजनलाल शर्मा ने 676 करोड़ के 77 कार्यों को दी मंजूरी

हैलो सरकार न्यूज, जयपुर। राजस्थान में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व

में वर्ष 2026-27 की बजट घोषणाओं को तेजी से धरातल पर उतारते हुए प्रदेश के 33 से अधिक जिलों में 77 सड़क निर्माण और उन्नयन कार्यों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं पर कुल 676.74 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में सड़क संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों तक आवागमन पहले से अधिक सुगम हो सकेगा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जारी स्वीकृतियों के अनुसार इन कार्यों के तहत करीब 686.42 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसमें राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण संपर्क मार्ग शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य दूरदराज क्षेत्रों को बेहतर सड़क सुविधा से जोड़ना और यातायात को सुरक्षित व सुविधाजनक बनाना है।

इन जिलों को मिलेगा लाभ

इन स्वीकृत कार्यों का लाभ अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, बालोतरा, बूंदी, चूरू, दौसा, डीग, डूंगरपुर, डीडवाना-कुचामन, जालोर, झुंझुनूं, जोधपुर, करौली, कोटपूतली, नागौर, पाली, फलोदी, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, सलूम्बर, सिरोही और उदयपुर समेत 33 से अधिक जिलों को मिलेगा। इन क्षेत्रों में लंबे समय से खराब या संकरी सड़कों की समस्या बनी हुई थी, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता था।

पर्यटन-व्यापार को मिलेगा बढ़ावा

सरकार का मानना है कि सड़क ढांचा मजबूत होने से न केवल आमजन को राहत मिलेगी, बल्कि व्यापार, पर्यटन और कृषि गतिविधियों को भी गति मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क होने से किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी, वहीं विद्यार्थियों और मरीजों को भी बेहतर परिवहन सुविधा मिल सकेगी।

सड़क निर्माण को सरकार दे रही प्राथमिकता

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2026-27 में सड़क अवसंरचना को विशेष प्राथमिकता दी है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर क्षेत्र को मजबूत सड़क नेटवर्क से जोड़ना है, ताकि विकास की गति गांवों तक पहुंच सके। 77 सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी को इसी दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में इन परियोजनाओं के पूरा होने से राजस्थान का सड़क तंत्र और अधिक आधुनिक तथा मजबूत नजर आएगा।

होर्मुज में चार जहाजों पर ईरानी सेना ने की गोलीबारी, दुश्मन के विमान को भी गिराने का दावा

तेहरान। पश्चिम एशिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। गाजा में बढ़ते सैन्य अभियान, इस्राइल-ईरान के बीच लगातार बढ़ रही तल्खी, लेबनान में फिर तेज होते हमले और अमेरिका की बढ़ती दखल ने पूरे इलाके का तनाव कई गुना बढ़ा दिया है। हालात ऐसे हैं कि हर कुछ घंटे में कोई नया हमला, बड़ा बयान या कूटनीतिक हलचल दुनिया की सुर्खियां बन रही है। तेल कारोबार से लेकर वैश्विक राजनीति तक, हर मोर्चे पर इसका असर दिखाई देने लगा है। पूर्व अमेरिकी नौसैनिक अधिकारी हरलान उलमैन का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच अगले 60 दिनों में समझौता होना मुश्किल है। दोनों देशों के बीच यूरेनियम और होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने को लेकर विवाद चल रहा है।

हाईवे से हटेंगे 430 से ज्यादा अवैध निर्माण; बुलडोजर चलाने की तैयारी

हैलो सरकार न्यूज

उदयपुर। उदयपुर में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। एनएचएआई के 370 और पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी एनएच के अधीन 67 अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए गए हैं। देबारी-काया मार्ग पर अवैध पार्किंग के खिलाफ भी जल्द विशेष कार्रवाई होगी

उदयपुर शहर और राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर उदयपुर जिला प्रशासन अब सख्त रुख अपनाने जा रहा है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को लंबित अतिक्रमणों को जल्द हटाने के निर्देश देते हुए कार्रवाई में तेजी लाने को कहा है। इसके तहत एनएचएआई क्षेत्र में 370 और पीडब्ल्यूडी एनएच क्षेत्र में 67 अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया अब तेज की जाएगी।

कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए

यह निर्देश जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए गए। बैठक में जिला कलेक्टर ने तहसीलवार चिन्हित अतिक्रमणों की लोकेशन आधारित जानकारी ली और संबंधित

विभागों को शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की निगरानी के लिए एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही प्रत्येक सप्ताह कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

एसपी ने पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि किसी चिन्हित स्थल पर धार्मिक संरचना मौजूद है, तो राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाकर उसे स्थानांतरित किया जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने कार्रवाई के दौरान पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेन ड्राइविंग से जुड़े साइनेज और होर्डिंग्स नहीं लगाए जाने पर उन्होंने एनएचएआई अधिकारियों पर नाराजगी जताई।

चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स की भी समीक्षा हुई

बैठक में आईराइड के माध्यम से चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स की भी समीक्षा की गई। सड़क हादसों वाले इन स्थानों पर रोड इंजीनियरिंग सुधार जल्द करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए। इसके अलावा देबारी से काया मार्ग के बीच अवैध पार्किंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। शहर के चिन्हित स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर पेंसिल डिवाइडर लगाने और उसका भौतिक सत्यापन पुलिस विभाग से कराने को भी कहा गया है।

जल प्राणिमात्र की मूलभूत आवश्यकता, जल संरक्षण हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी -जोगाराम पटेल

जल संरक्षण के लिए सभी उद्यमियों, सामाजिक संगठनों, किसानों एवं आमजन से सहयोग की अपील

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर । वंदे गंगा जल संरक्षण ,जन अभियान के तहत जिला प्रशासन व जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा सीएसआर कार्यशाला का आयोजन विधि, संसदीय एवं जयपुर जिले की प्रभारी मंत्री श्री जोगाराम पटेल के मुख्य आतिथ्य में गुरुवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुआ। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जल धरती के प्राणिमात्र की मूलभूत आवश्यकता है। जल है तो कल है ,जल है तो जीवन है। जल को भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षण करना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए उन्होंने जिले के सभी उद्यमियों, किसानों, सामाजिक संगठनों ,कार्मिकों एवं आमजन से जल संरक्षण के इस पुनीत कार्य में पूरे तन,मन व धन से जुड़कर इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देकर जयपुर जिले को जल के क्षेत्र में अग्रणी जिला बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इस दौरान उपस्थित सभी सभी लोगों

को जल संरक्षण की शपथ भी दिलवाई।

कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे जिला कलेक्टर संदेश नायक ने प्राणिमात्र के लिए जल की महता बताते हुए सभी उद्यमियों से जल संरक्षण कार्यों में अधिक से अधिक धनराशि दान करने की अपील की है।

इस अवसर पर जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक सुभाष शर्मा ने अपने स्वागतीय भाषण में 25 मई से 5 जून 2026 तक संचालित इस अभियान में सभी उद्यमियों को व्यापक व सक्रियता से भाग लेने की अपील की है।

इस दौरान वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक डॉ मलेंद्र चौहान ने अधिक भूजल के दोहन से उत्पन्न खतरे व जल ग्रहण विभाग के अधीक्षण अभियंता गोपाल प्रसाद जैन ने बारिश की एक-एक बूंद को सहेजने ने की महत्ता पर प्रस्तुति दी।

वही पानी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद् पदम श्री लक्ष्मण सिंह लापोडिया वाले व धरती अमृत वाले पदम श्री सुण्डाराम व उद्यमियों ने जल संरक्षण, पौधारोपण व पर्यावरण संरक्षण के संबंध में उनके द्वारा किए गए कार्यों से सभी को अवगत कराया। इस अवसर पर महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, जयपुर शहर डॉक्टर अनुकृति सिंह ने उद्यमियों और गो प्रतिनिधियों को कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उपवन संरक्षक वी के तन कुमार,अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम विनीता सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ आशीष कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं जिले के उद्यमी व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

रंग ला रहे मुख्यमंत्री के प्रयास-टीबी मुक्त होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा राजस्थान

हैलो सरकार न्यूज, जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान टीबी मुक्त होने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के टीबी मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी दिशा में संचालित 'टीबी मुक्त भारत अभियान-100 दिवसीय विशेष अभियान' में राजस्थान ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इस वर्ष 24 मार्च को शुरू हुए इस अभियान में मात्र दो माह में प्रदेश में करीब 19 लाख व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 'निरामय राजस्थान' के विजन के तहत टीबी जैसी गंभीर बीमारी के उन्मूलन के लिए व्यापक स्तर पर स्क्रीनिंग, शीघ्र जांच, जनजागरूकता, पोषण सहायता एवं सामुदायिक सहभागिता को प्राथमिकता दी जा रही है। जनभागीदारी, तकनीक एवं संवेदनशीलता के साथ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाकर हम टीबी की इस जंग को हर हाल में जीतेंगे। 11 हजार गांवों में अभियान, अब तक 5 हजार शिविर, 16 लाख से ज्यादा एक्सरे

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि प्रदेशभर में 24 मार्च से 11,328 हाई रिस्क गांवों एवं वार्डों में विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अभियान के अंतर्गत प्रदेश में अब तक करीब 5 हजार आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 18.93 लाख से अधिक व्यक्तियों की टीबी स्क्रीनिंग की गई। समय पर एवं सटीक जांच करने के लिए 16.51 लाख चेस्ट एक्स-रे तथा 1.41 लाख से अधिक एनएएटी जांचें सुनिश्चित की गईं।

32 हजार से अधिक नए रोगियों की पहचान

उन्होंने बताया कि सक्रिय केस खोज (एक्टिव केस फाइंडिंग) गतिविधियों के माध्यम से अभियान के दौरान कुल 32,102 नए टीबी रोगियों की पहचान की गई। इनमें 10,457 ऐसे मरीज शामिल हैं, जिनमें किसी प्रकार के लक्षण नहीं थे। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि स्वास्थ्य विभाग की सक्रिय एवं वैज्ञानिक कार्यप्रणाली को दर्शाती है।

संवेदनशील एवं उच्च जोखिम वाली आबादी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से अधिक से अधिक व्यक्तियों की एक्सरे एवं नाट मशीन से जांच की जा रही है।

12 हजार से अधिक को टीपीटी

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण एवं आवश्यकता आधारित उपचार सुनिश्चित करने हेतु डिफरेंशिएटेड टीबी केयर के अंतर्गत 32 हजार से अधिक पात्र मरीजों में से 16 हजार 500 से अधिक मरीजों का आकलन किया गया, जो 51 प्रतिशत उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि टीबी संक्रमण की रोकथाम के लिए टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट (टीपीटी) के अंतर्गत 12 हजार 535 व्यक्तियों को टीपीटी आरंभ किया गया।

उन्होंने बताया कि टीबी मरीजों के उपचार में पोषण सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से संचालित पोषण सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2026 से अब तक करीब 46 हजार सहमति प्राप्त टीबी मरीजों में से करीब 38 हजार लाभार्थियों को न्यूट्रिशन किट वितरित की गईं, जो करीब 83 प्रतिशत उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि निक्षय मित्र पहल के तहत अभियान अवधि में 2 हजार नए निक्षय मित्र पंजीकृत किए गए तथा सामुदायिक सहयोग से करीब 34 हजार फूड बास्केट टीबी मरीजों को वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि यह समाज एवं सरकार की साझी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण है।

जनजागरूकता पर विशेष फोकस, वर्ष 2025 में लक्ष्य से ज्यादा टीबी मरीज अधिसूचित

निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि टीबी उन्मूलन के लिए जनभागीदारी एवं जनजागरूकता पर विशेष फोकस किया जा रहा है। अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप दिया गया है। इसके अंतर्गत राज्यभर में 7500 स्कूल स्तरीय एवं 1363 कॉलेज स्तरीय गतिविधियां आयोजित की गईं। साथ ही करीब एक हजार माय भारत स्वयंसेवकों एवं 7 हजार से अधिक जनप्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। डॉ. शर्मा ने बताया कि राजस्थान ने वर्ष 2025 में कुल 1.63 लाख टीबी मरीजों की अधिसूचना करते हुए निर्धारित लक्ष्य का 102 प्रतिशत हासिल किया है। साथ ही प्रदेश की 6,547 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है, जो राज्य के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है।

हाइड्रोजन की रफ्तार पर दौड़ेगा आत्मनिर्भर भारत

(लेखक-विनोद कुमार सिंह 'तकियावाला)

भारतीय रेल की हरित क्रांति : जिंद-सोनीपत सेक्शन पर शुरू होने जा रही देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन,स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक तकनीक और पर्यावरण संरक्षण के संगम से विकसित भारत की नई दिशा

भारत आज केवल आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर नहीं है,बल्कि विज्ञान,तकनीक, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भी विश्व को नई दिशा देने का कार्य कर रहा है। एक समय था जब भारतीय रेल केवल यात्रियों और माल ढुलाई का माध्यम मानी जाती थी,लेकिन आज वही भारतीय रेल आधुनिक भारत की बदलती तस्वीर,तकनीकी आत्मविश्वास और हरित विकास की सबसे बड़ी प्रतीक बन चुकी है।इसी क्रम में भारतीय रेलवे ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली है।हरियाणा के जिंद-सोनीपत रेलखंड पर देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन शुरू होने जा रही है। यह केवल एक नई ट्रेन नहीं,बल्कि भारत के ऊर्जा भविष्य,पर्यावरणीय जिम्मेदारी और आत्मनिर्भर तकनीक की नई उड़ान है।भारतीय रेलवे द्वारा स्वीकृत यह 10 कोच वाली अत्याधुनिक ट्रेन 1200 किलोवाट क्षमता वाले इंजन से संचालित होगी तथा इसकी अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह ट्रेन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेगी,क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलने वाली इस ट्रेन से केवल जलवाष्प का उत्सर्जन होगा।आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते प्रदूषण जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है।पेट्रोल और डीजल आधारित परिवहन व्यवस्था ने वायु प्रदूषण को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है। ऐसे समय में भारत द्वारा हाइड्रोजन ऊर्जा आधारित रेल सेवा की शुरुआत एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

> यही कारण है कि विश्वभर में इसे भविष्य की सबसे स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा तकनीकों में शामिल किया जा रहा है।भारतीय रेलवे की यह पहल देश को हरित परिवहन व्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाएगी। इससे रेलवे के कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को भी बढ़ावा मिलेगा।भारत पहले ही वर्ष 2070 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित कर चुका है और यह परियोजना उसी संकल्प को मजबूती प्रदान करती है।देश के करोड़ों रेल यात्रियों के लिए भी यह पहल गर्व और भावनात्मक जुड़ाव का विषय है।

वर्तमान समय में पूरी दुनिया ऊर्जा संकट की चुनौती से भी जूझ रही है।रूस-यूक्रेन युद्ध,पश्चिम एशिया में तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर रहना भविष्य के लिए सुरक्षित नहीं है। भारत जैसे विशाल देश के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता अब केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं,बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थायी विकास का महत्वपूर्ण विषय बन चुकी है। ऐसे समय में हाइड्रोजन ऊर्जा भविष्य की सबसे बड़ी संभावनाओं के रूप में उभर रही है।हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में धुआं,कार्बन या जहरीली गैसें नहीं निकलतीं,बल्कि केवल जलवाष्प उत्पन्न होती है। यही कारण है कि विश्वभर में इसे भविष्य की सबसे स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा तकनीकों में शामिल किया जा रहा है।भारतीय रेलवे की यह पहल देश को हरित परिवहन व्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाएगी। इससे रेलवे के कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को भी बढ़ावा मिलेगा।भारत पहले ही वर्ष 2070 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित कर चुका है और यह परियोजना उसी संकल्प को मजबूती प्रदान करती है।देश के करोड़ों रेल यात्रियों के लिए भी यह पहल गर्व और भावनात्मक जुड़ाव का विषय है। भारतीय रेल केवल यात्रा का साधन नहीं,बल्कि देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन रेखा मानी जाती है। गांव से शहर,किसान से मजदूर,छात्र से व्यापारी तक हर वर्ग का व्यक्ति भारतीय रेल से जुड़ा हुआ है।ऐसे में जब यात्री यह महसूस करेंगे कि उनकी यात्रा अब प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण हितैषी तकनीक से हो रही है,तो यह उनके भीतर भी प्रकृति संरक्षण के प्रति नई चेतना पैदा करेगा।आज का जागरूक यात्री केवल सुविधाजनक यात्रा नहीं चाहता,बल्कि वह ऐसी व्यवस्था भी चाहता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण छोड़ सके। यही कारण है कि पर्यावरण प्रेमियों,युवाओं और वैज्ञानिक समुदाय के बीच हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है। यह पहल लोगों को यह संदेश भी देती है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चल सकते हैं।हाइड्रोजन आधारित रेल प्रणाली अभी विश्व में प्रारंभिक अवस्था में है। वर्तमान समय में केवल कुछ ही देश इस तकनीक का सफल परीक्षण या संचालन कर रहे हैं। जर्मनी,जापान,चीन और अमेरिका जैसे विकसित देशों के बाद अब भारत भी इस विशेष श्रेणी में शामिल हो गया है।यह उपलब्धि इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत ने केवल तकनीक आयात करने तक स्वयं को सीमित नहीं रखा,बल्कि स्वदेशी स्तर पर हाइड्रोजन ट्रेन और उससे जुड़ी आधारभूत संरचना विकसित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है।जिंद में स्थापित स्वदेशी हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग सुविधा भारत की तकनीकी क्षमता,वैज्ञानिक सोच और आत्मनिर्भर भारत अभियान का जीवंत उदाहरण है। यह परियोजना फ्रमेक इन इंडियाफ्र और फ्रआत्मनिर्भर भारतफ्र जैसे राष्ट्रीय अभियानों को नई ऊर्जा प्रदान करती है।

हरियाणा के जिंद-सोनीपत रेलखंड को इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए पायलट रूट के रूप में चुना गया है।जिंद में आधुनिक हाइड्रोजन स्टोरेज एवं रिफ्यूलिंग स्टेशन विकसित किया गया है,जहां हाइड्रोजन गैस का सुरक्षित भंडारण और ट्रेन में ईंधन भरने की व्यवस्था की गई है।पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (क्कश्वस्ह्र) ने इस परियोजना के लिए आवश्यक सुरक्षा लाइसेंस भी प्रदान कर दिया है। हाइड्रोजन गैस अत्यधिक संवेदनशील मानी जाती है,इसलिए इसके सुरक्षित संचालन के लिए विशेष तकनीकी प्रबंध किए गए हैं।रिफ्यूलिंग स्टेशन पर आधुनिक हाइड्रोजन कम्प्रेशन सिस्टम लगाया गया है। साथ ही बैकअप कम्प्रेसर यूनिट की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है ताकि संचालन में किसी प्रकार की बाधा न आए।सुरक्षा की दृष्टि से हाइड्रोजन लीकेज डिटेक्टर,फ्लेम डिटेक्टर और अन्य अत्याधुनिक सेंसर लगाए गए हैं।इन उपकरणों की नियमित जांच और साफ- सफाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि किसी भी दुर्घटना की संभावना समाप्त हो सके।भारतीय रेलवे ने इस परियोजना में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। .रेलवे डिजाइन एवं मानक संगठन (ऋस्ह्र) द्वारा संचालन और रखरखाव से संबंधित विस्तृत मैनुअल तैयार किए गए हैं।शकूरबस्ती में प्रस्तावित मेंटेनेंस सुविधा के लिए भी विशेष सुरक्षा मानक निर्धारित किए गए हैं। रेलवे ने 24 घंटे निगरानी व्यवस्था, नियमित सुरक्षा ऑडिट और प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित की है।प्रारंभिक चरण में प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ ट्रेन के साथ मौजूद रहेगा ताकि किसी भी तकनीकी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके। यह व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि भारतीय रेलवे केवल तकनीकी प्रयोग नहीं कर रही,बल्कि सुरक्षा और विश्वसनीयता को भी समान महत्व दे रही है।भारत लंबे समय से पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर निर्भर रहा है। इससे देश पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और वैश्विक परिस्थितियों का सीधा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा प्रणाली भविष्य में इस निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यदि रेलवे,बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थाओं में हाइड्रोजन तकनीक का व्यापक उपयोग शुरू होता है,तो भारत ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बन सकेगा।विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा शक्ति बन सकता है। भारत के पास सौर और पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं,जिनका उपयोग कर पर्यावरण अनुकूल ग्रीन हाइड्रोजन तैयार किया जा सकता है।हाइड्रोजन ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार से केवल रेलवे ही नहीं,बल्कि उद्योग,रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलेगा। हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र,स्टोरेज सुविधा,तकनीकी उपकरण और मेंटेनेंस सेवाओं के कारण नए उद्योग विकसित होंगे।

इससे इंजीनियरिंग,तकनीकी प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। भारत के युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को आधुनिक तकनीक के साथ कार्य करने का अवसर मिलेगा।यदि भविष्य में हाइड्रोजन उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचता है,तो वहां नई आर्थिक गतिविधियां भी विकसित होंगी,जिससे ग्रामीण भारत के विकास को नई गति मिलेगी।पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रेलवे ने अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। वंदे भारत ट्रेन,अमृत भारत स्टेशन योजना,डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर,रेलवे विद्युतीकरण और अब हाइड्रोजन ट्रेन—ये सभी इस बात का संकेत हैं कि भारतीय रेलवे अब केवल परिवहन सेवा नहीं, बल्कि विकसित भारत की विकास शक्ति बन चुकी है।भारत ने सदैव विश्व को फ्रवसुधैव कुटुम्बकम्फ्र और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया है। हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना उसी सोच का आधुनिक स्वरूप है। यह पहल दर्शाती है कि भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं,बल्कि नवाचार और समाधान प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र बन रहा है।निस्संदेह,जिंद-सोनीपत रेलखंड से शुरू होने वाली यह ऐतिहासिक यात्रा भारत की ऊर्जा क्रांति का मजबूत आधार बन सकती है।हाइड्रोजन की शक्ति से दौड़ती यह ट्रेन केवल पटरियों पर नहीं चलेगी,बल्कि विकसित, आत्मनिर्भर और हरित भारत के सपनों को भी नई गति प्रदान करेगी।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं।)

संपादकीय

मूल्यांकन पर आंच

अभी नीट प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्रों के लीक होने और परीक्षा रद्द होने की सुर्खियों की स्याही सूखी भी न थी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की मूल्यांकन प्रणाली सवालों के घेरे में आ गई। निश्चय ही ये घटनाक्रम छात्रों और प्रतियोगियों के परीक्षा व्यवस्था पर भरोसे को कम ही कर रहे हैं। आपदा में अवसर की तलाश में रहने वाले राजनीतिक दलों को छोड़ भी दें, तो भी आम लोग भी सीबीएसई की मूल्यांकन पद्धति पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल, सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम प्रणाली में खामियों और विसंगतियों को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं। कक्षा बारह के कुछ छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत अपलोड की गई स्कैन प्रतियों और उनकी उत्तर पुस्तिकाओं में विसंगति सामने आने का खुलासा किया है। निश्चित रूप से यह प्रकरण महज एक तकनीकी समस्या से कहीं अधिक का मामला है। यह भारत की उस शीर्ष परीक्षा प्रणाली की बढ़ती विफलता की चेतावनी है, जो लाखों छात्रों के भविष्य का निर्धारण करती है। इस घटनाक्रम में एक छात्र वेदांत श्रीवास्तव का मामला विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि सीबीएसई ने स्वयं स्वीकार किया है कि गलत उत्तर पुस्तिका भेजी गई थी। हालांकि, मामला तूल पकड़ता देख उसे बाद में सही उत्तर पुस्तिका भेज दी गई। इसी तरह एक अन्य परीक्षार्थी, संजना को भी सीबीएसई की तरफ से कमोबेश ऐसी ही प्रतिक्रिया मिली है। भला हो सोशल मीडिया का जो इन मुद्दों को देश की जनता के सामने तुरंत ले आता है और देश में इससे एक जनमत बनाने का अवसर मिलता है। हालांकि, यह स्वागत योग्य है कि सीबीएसई ने इन प्रणालीगत त्रुटियों को स्वीकार तो किया। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस लापरवाही के लिये जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अन्यथा लापरवाही व गलती का यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सीबीएसई को अपनी साख बचाये रखने के लिये इस दिशा में समय रहते सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यहां सवाल उठता है कि सीबीएसई जैसी परीक्षा नियामक संस्था ने अपने स्तर पर खामियों को दूर करने के लिये कारगर तंत्र क्यों विकसित नहीं किया। वह तब ही जागती है जब मीडिया में घटना सुर्खियां बनती है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सीबीएसई ने तब कार्रवाई की और सुधारात्मक कदम उठाये, जब प्रभावित छात्रों ने इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चलाया। निश्चित रूप से एक निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली में इतना लचीलापन होना चाहिए कि छात्रों के आक्रोश के सार्वजनिक होने, राजनीतिक टीका-टिप्पणी सामने आने या ऑनलाइन अभियान चलने से पहले समस्या का निराकरण हो जाए। हालिया घटनाक्रम का एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह भी है कि सीबीएसई की लापरवाही का शिकार बने वेदांत को अपनी बात उठाने पर बुरी तरह लांछित किया। कुछ सोशल मीडिया वीरों ने उसकी मुखरता से आवाज उठाने की कोशिश को देश विरोधी तक ही नहीं कहा, बल्कि कुछ ने तो उसे पाकिस्तानी तक कह दिया। यह तंत्र के बचाव में उतरने की अंधभक्ति ही है कि न्याय के लिये आवाज उठाने के लिये पीड़ित भारतीय नागरिक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की असफल कोशिश हो। क्या न्याय के लिये आवाज उठाने वाले छात्रों को इसलिए अपमानित व प्रताड़ित होना चाहिए क्योंकि उसकी शिकायत सामने आने के बाद देश के नामचीन संगठनों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है? वास्तव में इन छात्रों के मामले में आई खामियों की व्यापक स्तर पर पड़ताल होनी चाहिए।

गुजरात में इबोला की आशंका से बढ़ी सतर्कता

(लेखक- कांतिलाल मांडोत)

- कांगो से आए युवक में संक्रमण की आशंका से स्वास्थ्य तंत्र अलर्ट

गुजरात में इबोला वायरस की आशंका ने स्वास्थ्य विभाग और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अफ्रीकी देश कांगो से लौटे एक 37 वर्षीय युवक में इबोला जैसे लक्षण पाए जाने के बाद पूरे राज्य का स्वास्थ्य तंत्र अलर्ट मोड पर आ गया है। युवक को पहले वडोदरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत और लक्षणों को देखते हुए बाद में अहमदाबाद सिविल अस्पताल में विशेष निगरानी के तहत भर्ती किया गया। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संपर्क ट्रेसिंग और निगरानी की प्रक्रिया तेज कर दी है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मरीज करीब दस दिन पहले कांगो से मुंबई पहुंचा था। मुंबई में कुछ दिन रुकने के बाद वह सिलवासा और दमण क्षेत्र गया तथा बाद में 22 मई को वडोदरा पहुंचा। 26 मई को उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। लगातार बुखार और वायरल हेमरेजिक फीवर जैसे लक्षण सामने आने पर डॉक्टरों ने उसे संदिग्ध इबोला मरीज मानते हुए विशेष निगरानी में रखा। मरीज की जांच रिपोर्ट में लीवर एंजाइम्स एसजीपीटी और एसजीओटी का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया। इसके अलावा प्लेटलेट्स भी सामान्य से कम दर्ज किए गए, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता और बढ़ गई।

इबोला वायरस दुनिया के सबसे खतरनाक संक्रमणों में गिना जाता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क से फैलता है और तेजी से गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। अफ्रीकी देशों में समय-समय पर इसके प्रकोप की खबरें आती रही हैं। यही कारण है कि कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान जैसे देशों से आने वाले यात्रियों की विशेष जांच की जा रही है। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की है ताकि किसी भी संभावित संक्रमित व्यक्ति की समय रहते पहचान की जा सके।

अहमदाबाद सिविल अस्पताल में मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। डॉक्टरों की एक विशेष टीम उसकी निगरानी कर रही है। अस्पताल प्रशासन ने संक्रमण से बचाव के लिए विशेष प्रोटोकॉल लागू किए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट और अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं ताकि संक्रमण फैलने का खतरा कम किया जा सके। मरीज की अंतिम जांच रिपोर्ट आने तक उसे पूरी तरह अलग निगरानी में रखा जाएगा।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सरकार पूरी तरह सतर्क है और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने बताया कि मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान की जा रही है। संपर्क में आए लोगों में कुछ को बुखार की शिकायत भी मिली है, इसलिए उनकी मेडिकल जांच और निगरानी शुरू कर दी गई है। एक चिकित्सक और कुछ विदेशी नागरिकों के संपर्क में आने की जानकारी भी सामने आई है। इन सभी लोगों को स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रखा गया है।

अहमदाबाद मनपा संचालित एसवीपी अस्पताल में भी तीन संदिग्ध मरीजों को क्वारंटीन किया गया है। अस्पताल प्रशासन ने विशेष वार्ड तैयार कर रखा है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इलाज शुरू किया जा सके। डॉक्टरों का कहना है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। संक्रमण की पुष्टि होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

इबोला जैसी बीमारियां केवल स्वास्थ्य संकट ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी बन जाती हैं। कोविड महामारी के बाद लोगों में संक्रामक रोगों को लेकर संवेदनशीलता बढ़ी है। ऐसे में किसी भी संदिग्ध मामले की खबर तेजी से चिंता का कारण बन जाती है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि समय रहते जांच और निगरानी से संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट स्क्रीनिंग, अस्पताल निगरानी और संपर्क ट्रेसिंग जैसे कदम तेजी से शुरू किए हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार इबोला संक्रमण के शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार, कमजोरी, शरीर में दर्द, उल्टी और रक्तस्राव जैसी समस्याएं शामिल हो सकती हैं। यदि समय पर इलाज और आइसोलेशन न किया जाए तो यह वायरस गंभीर रूप ले सकता है। इसलिए विदेश यात्रा से लौटने वाले लोगों को किसी भी असामान्य लक्षण की स्थिति में तुरंत जांच करानी चाहिए और स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देनी चाहिए।

गुजरात सरकार की सक्रियता इस मामले में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी कर रहा है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि किसी भी संभावित संक्रमण से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। एयरपोर्ट और अस्पतालों में निगरानी बढ़ा दी गई है तथा मेडिकल टीमों को अलर्ट रखा गया है।

यह घटना एक बार फिर यह याद दिलाती है कि वैश्विक स्तर पर फैलने वाली बीमारियों का खतरा आज भी बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय यात्रा और बढ़ती आवाजाही के कारण किसी भी देश में संक्रमण पहुंचने की संभावना बनी रहती है। ऐसे समय में मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था और त्वरित कार्रवाई ही सबसे बड़ा बचाव साबित होती है।

फिलहाल पूरे राज्य की नजर मरीज की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हुई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अफवाहों से बचने की अपील कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सतर्कता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर किसी भी संभावित खतरे से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है।

(रु 103 जलवन्त टाउनशिप पूणा बॉम्बे मार्केट रोड, नियर नन्दालय हवेली सूरत मो 99749 40324 वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार-स्तम्भकार)

वैज्ञानिक बनने की चाह

किसी समय लंदन की एक बस्ती में एक अनाथ बालक रहता था। वह अखबार बेचकर किसी तरह अपना गुजारा करता था। कुछ समय बाद उसे एक जिल्दसाज की दुकान पर जिल्द चढ़ाने का काम मिल गया। उस बालक को पढ़ने का बहुत शौक था। वह पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाते समय महत्वपूर्ण बातें व जानकारियां पढ़ता रहता था। एक दिन जिल्द चढ़ाते समय उसकी नजर एक विद्युत संबंधी लेख पर पड़ी।

वह लेख उसे बहुत ही मनोरंजक लगा। उसने दुकान के मालिक से एक दिन के लिए वह पुस्तक मांग ली और रात भर में उस लेख के साथ ही पूरी पुस्तक भी पढ़ डाली। पुस्तक का उसके ऊपर गहरा असर पड़ा। इससे उसकी प्रयोग करने में जिज्ञासा बढ़ती गई और धीरे-धीरे वह अध्ययन एवं परीक्षण के लिए विद्युत संबंधी छोटी-मोटी चीजें इधर-उधर से जुटाने लगा। बालक की इस बारे में रुचि देखकर एक ग्राहक उससे बहुत प्रभावित हुआ। वह खुद भी विज्ञान में गहरी दिलचस्पी रखता था। एक दिन वह बालक को अपने साथ भौतिकशाप के प्रसिद्ध विद्वान डेवी का भाषण सुनाने ले गया। बालक ने डेवी की बातें ध्यान से सुनीं और उन्हें नोट भी किया। इसके बाद बालक ने उनके भाषण की समीक्षा करते हुए अपने कुछ परामर्श लिखकर डेवी के पास भेज दिए।

डेवी को बालक की सलाह बहुत पसंद आई। उन्होंने उसे अपने यंत्र व्यवस्थित करने के लिए अपने पास रख लिया। बालक उनके साथ रहने लगा। वह उनके सहयोगी और नौकर दोनों की भूमिका निभाता रहा। वह दिन भर कामों में व्यस्त रहता, रात को अध्ययन करता। थकान होने पर भी उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती थी। वह भौतिकी के क्षेत्र में खासकर विद्युत के क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहता था। आखिरकार अपनी मेहनत और संकल्प से उसने अपना सपना पूरा किया। वह एक महान वैज्ञानिक बन गया। आज दुनिया उस बालक को माइकल फैराडे के नाम से जानती है।

विचार मंथन

शक्ति और अधिकार के साथ जवाबदेही, पहले सजा फिर सुनवाई, न्याय सिद्धांत नहीं

(लेखक- सनत जैन)

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां सत्ता का अंतिम स्रोत जनता मानी गई है। संविधान ने नागरिकों को केवल अधिकार ही नहीं दिए, बल्कि राज्य की शक्तियों की सीमाएं भी निर्धारित की हैं। विधायिका कानून बना सकती है, कार्यपालिका उनका क्रियान्वयन कर सकती है और न्यायपालिका उनकी संवैधानिक समीक्षा कर सकती है, लेकिन इन तीनों संस्थाओं के ऊपर संविधान सर्वोच्च माना गया है। इसी कारण मौलिक अधिकारों को लोकतंत्र की आत्मा कहा गया है। संविधान स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था करता है कि कोई भी ऐसा कानून या प्रशासनिक आदेश वैध नहीं माना जा सकता जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। न्यायपालिका को इसी उद्देश्य से न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया ताकि वह संविधान की मूल भावना की रक्षा कर सके। भारतीय इतिहास में अनेक अवसरों पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने सरकारों के निर्णयों को असंवैधानिक घोषित करते हुए नागरिक अधिकारों की रक्षा की है। आपातकाल का उदाहरण भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे विवादास्पद अध्याय माना जाता है। 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं पर व्यापक प्रतिबंध लगाए गए थे, हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया और प्रेस की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई। हालांकि संविधान में आपातकाल का प्रावधान मौजूद था, लेकिन बाद में जनता ने चुनाव के माध्यम से अपनी असहमति व्यक्त की और सत्ता परिवर्तन हुआ। यह घटना इस बात का प्रमाण भी बनी कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता के हाथ में होता है। वर्तमान समय में भी विभिन्न कानूनों, जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली, लंबी न्यायिक प्रक्रियाओं, बेरोजगारी, परीक्षा घोटालों और प्रशासनिक सख्ती को लेकर समाज के अलग-अलग वर्गों में असंतोष दिखाई देता है। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी तथा आंदोलनों पर बल प्रयोग जैसी घटनाओं ने अविश्वास का वातावरण पैदा किया है। जब नागरिकों को यह महसूस होने लगे कि उनकी समस्याओं का समाधान संस्थागत माध्यमों से नहीं हो रहा, तब सामाजिक तनाव बढ़ने लगता है। हालांकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह आवश्यक है कि आलोचना तथ्यों और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर हो। न्यायपालिका, चुनाव आयोग, संसद, मीडिया और प्रशासन जैसी संस्थाओं पर विश्वास लोकतंत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि इन संस्थाओं के प्रति व्यापक अविश्वास उत्पन्न होता है, तो समाज में अराजकता और भीड़तंत्र की स्थिति पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। पिछले एक दशक में संवैधानिक संस्थाओं एवं कार्यपालिका के प्रमुख पदों पर बैठे लोग सरकार के दबाव में काम करते थे। अब यही आरोप न्यायपालिका पर भी लगने लगे हैं। अदालतें सरकारी और पूंजीपतियों के दबाव में निर्णय करती है। यह धारणा आमजन को बनने लगी है। इससे बार-बार लोकतंत्र एवं संविधान खतरे में है। इस तरह की धारणा बनने लगी है। लोकतंत्र केवल कानूनों से नहीं चलता, बल्कि जनता के विश्वास, संवाद और संस्थाओं की निष्पक्षता से चलता है। सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे नागरिक अधिकारों का सम्मान करें, पारदर्शिता बनाए रखें और युवाओं की समस्याओं का समाधान करें। वहीं नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वे अपने अधिकारों की लड़ाई लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीकों से लड़ें। संविधान का मूल उद्देश्य सत्ता और जनता के बीच संतुलन बनाए रखना है, और यही संतुलन लोकतंत्र को मजबूत बनाता है।

> 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं पर व्यापक प्रतिबंध लगाए गए थे, हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया और प्रेस की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई। हालांकि संविधान में आपातकाल का प्रावधान मौजूद था, लेकिन बाद में जनता ने चुनाव के माध्यम से अपनी असहमति व्यक्त की और सत्ता परिवर्तन हुआ।

गोयल ने कनाडा को दिया दोहरी-डिग्री का प्रस्ताव, संबंधों में 'पुनर्संतुलन' पर जोर

टोरंटो में केंद्रीय मंत्री ने कहा, छात्रों के लिए दोहरी-डिग्री व्यवस्था हो

टोरंटो ।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी कनाडा यात्रा के दौरान शैक्षिक सहयोग बढ़ाने पर जोर देते हुए कनाडा को दोहरी-डिग्री व्यवस्था शुरू करने का सुझाव दिया है। टोरंटो विश्वविद्यालय में अपने संबोधन में गोयल ने मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए भारत-कनाडा संबंधों में राजनीतिक पुनर्संतुलन के उपयुक्त समय का भी जिक्र किया। गोयल ने ऐसे कार्यक्रमों पर तेजी से काम करने का सुझाव दिया, जिनमें छात्र एक साल कनाडा में पढ़ाई कर सकें और फिर भारत लौटकर देश के विकास में योगदान दें। उन्होंने कनाडा के युवाओं को भारत आकर यहां हो रहे विकास कार्यों को करीब से देखने का भी आमंत्रण दिया। दोहरी-डिग्री व्यवस्था के तहत छात्र आंशिक पढ़ाई भारत और आंशिक कनाडा में करके दोनों संस्थानों से मान्यता प्राप्त डिग्री पा सकते हैं। इस अवसर पर गोयल ने निवेश आकर्षित करने की अपील करते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने 2047 तक प्रति व्यक्ति आय को 20,000 डॉलर तक पहुंचाने और विनिर्माण-बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश का लक्ष्य बताया। गोयल ने गणितीय गणना के आधार पर अनुमान जताया कि 7 फीसदी की वृद्धि दर बनाए रखने पर भारत की अर्थव्यवस्था अगले 25 वर्षों में लगभग आठ गुना बढ़कर 30 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकती है।

ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी और राज्यों के प्रतिबंध का अधिकार वैध- एससी

कंपनियों पर पिछली तारीख से भारी-भरकम कर का बोझ

नई दिल्ली।

सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को एक बड़ा झटका दिया है। न्यायालय ने गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लगाए जाने वाले दांव के समूचे अंकित मूल्य पर पिछली तारीख से 28 फीसदी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने राज्यों को पैसों वाले ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाने के अधिकार को भी वैध ठहराया है। इन फैसलों से भारत में बची हुई गेमिंग कंपनियों के संचालन पर गंभीर संकट गहरा गया है। न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि यह कर संवैधानिक रूप से वैध है और जीएसटी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। पीठ ने स्पष्ट किया कि फैंटेसी स्पोर्ट्स सहित ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियां, जिनमें अनिश्चित परिणामों पर दांव लगाया जाता है, जीएसटी ढांचे के तहत सट्टेबाजी और जुए की श्रेणी में आती हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर करीब 91,684 करोड़ रुपये का कर बकाया है, जो ब्याज और जुर्माने सहित संभावित रूप से दोगुना हो सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को महज मध्यस्थ नहीं माना जा सकता और उनकी गतिविधियां जीएसटी व्यवस्था के दायरे में आती हैं। अदालत ने पिछली तारीख से लागू होने वाले कर संशोधनों को भी वैध ठहराया। गेमिंग कंपनियों ने 28 फीसदी जीएसटी को पिछली तारीख से लागू करने को चुनौती दी थी। इन निर्णयों से उन गेमिंग कंपनियों पर दबाव और बढ़ गया है जो पहले ही अपना कारोबार समेट चुकी हैं या कम कर चुकी हैं।

ईंधन सब्सिडी दुरुपयोग पर सरकार का शिकंजा

औद्योगिक उपभोक्ता खुदरा ईंधन खरीद रहे, डीलर भी कर रहे कालाबाजारी

नई दिल्ली । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पश्चिम एशिया संकट पर हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में खुदरा ईंधन के दुरुपयोग और कालाबाजारी के गंभीर मामले सामने आए हैं। इसमें पाया गया कि औद्योगिक उपभोक्ता सब्सिडी वाले खुदरा ईंधन का लाभ उठा रहे हैं, जिससे तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को भारी दैनिक नुकसान हो रहा है। मंत्रियों के अनौपचारिक समूह (आईजीओएम) की बैठक की कार्यवाही पर जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह खुलासा हुआ कि औद्योगिक उपभोक्ता सब्सिडी वाली कीमत का फायदा उठाने के लिए औद्योगिक ईंधन की बजाय खुदरा ईंधन खरीद रहे हैं। इसके साथ ही कुछ डीलरों द्वारा कालाबाजारी के भी मामले सामने आए हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तेल विपणन कंपनियों और राज्य सरकारों ने जमीनी स्तर पर निगरानी तेज कर दी है और उद्योग संगठनों को भी इस काम से जोड़ा जा रहा है।

एचडीएफसी बैंक के शेयर लुढ़के, सरकारी एजेंसी को अनुचित भुगतान का आरोप

बैंक ने आरोपों का खंडन किया, आंतरिक नियंत्रण मजबूत होने का दावा

नई दिल्ली ।

एचडीएफसी बैंक के शेयरों में 2.6 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जब मीडिया रिपोर्टों में महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) नामक एक सरकारी एजेंसी को कथित रूप से अनुचित भुगतान का दावा किया गया। हालांकि, बैंक ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सभी लेनदेन स्थापित मानदंडों के अनुसार हुए हैं।

दिन के अंत में बैंक का शेयर 758.50 पर बंद हुआ, जो पिछले बंद से 2.63 फीसदी नीचे था। एक रिपोर्ट के अनुसार बैंक द्वारा की गई एक आंतरिक जांच में पाया गया कि वित्त वर्ष 2024 और 2025 में एमएसआरडीसी को डिफरेंशियल इंटरेस्ट'के रूप में वर्गीकृत विपणन व्यय के माध्यम से लगभग 45 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। किसी भी गलत काम से इनकार करते हुए, एचडीएफसी बैंक ने कहा कि उसके पास मजबूत आंतरिक निरीक्षण, लेखा परीक्षा और नियंत्रण प्रक्रियाएं और प्रणालियां हैं। बैंक ने एक बयान में कहा' कि बैंक के स्थापित मानदंडों के अनुसार सभी मुद्दों को निपटाया जाता है। हम चुनिंदा सामग्री के आधार पर कदाचार या जवाबदेही की किसी भी धारणा को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब बैंक में प्रशासन संबंधी सवाल उठे हैं, और पूर्व अंशकालिक अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती ने मार्च में इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद केकी मिस्त्री को तीन महीने के लिए अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

जेब से स्वास्थ्य खर्च में बढ़ोतरी, सरकार का अंशदान घटा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2022-23ः लोगों की जेब से खर्च बढ़कर 43.4 फीसद हुआ

नई दिल्ली ।

देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले कुल व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन इसमें लोगों द्वारा सीधे अपनी जेब से किया जाने वाला खर्च (आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर- ओओपीई) भी बढ़ा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2022-23 के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय में ओओपीई एक साल में 39.4 फीसदी (2021-22) से बढ़कर 43.4 फीसदी हो गया है। इसी अवधि में, स्वास्थ्य पर सरकार का अंश 48 फीसदी से घटकर 43.7 फीसदी रह गया है। यह पहली बार है जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुमानों में ओओपीई में वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो बढ़ती लागतों की ओर इशारा करता है। रिपोर्ट बताती है कि कोविड-19 महामारी के बाद पूर्ण रूप से खुलने के पहले साल (2022-23) में स्वास्थ्य, निदान और फार्मास्यूटिकल्स की उच्च लागत और मांग के कारण ओओपीई में यह वृद्धि हुई है।

बीमा क्लेम अब तेज और पारदर्शी, अधिकारियों की सीधी जवाबदेही

आईआरडीएआई सख्त, कंपनियों को 15, 30 और 60 दिन में देना होगा क्लेम अपडेट

मुंबई ।

बीमा नियामक भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने ग्राहकों की बीमा क्लेम संबंधी परेशानियों को कम करने के लिए कड़े नए नियम लागू किए हैं। अब बीमा कंपनियों को तय समय सीमा में क्लेम निपटाने होंगे और देरी होने पर वरिष्ठ अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय की जाएगी। इससे करोड़ों पॉलिसीधारकों को तेज और पारदर्शी सेवा मिलने की उम्मीद है। नए नियमों के तहत, बीमा कंपनियों के एमडी और सीईओ की जिम्मेदारी सीधे ग्राहक सेवा से जुड़ी है। उनका बोनस और अतिरिक्त वेतन अब इस बात पर निर्भर करेगा कि क्लेम कितनी तेजी व पारदर्शिता से निपटाए जा रहे हैं। कंपनियों को हर 15, 30 और 60 दिन में ग्राहकों को क्लेम की स्थिति बतानी होगी, जिससे उन्हें बेवजह कार्यालय के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त पॉलिसी में पता, मोबाइल नंबर या नॉमिनी बदलने जैसे कार्य अब 7 दिनों के भीतर पूरे करने होंगे; देरी होने पर इसे शिकायत माना जाएगा। आईआरडीएआई ने कंपनियों के कामकाज की निगरानी हेतु छह प्रमुख मानदंड भी तय किए हैं, जिनमें क्लेम सेटलमेंट रिकॉर्ड और शिकायत निपटान शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन सख्त नियमों से बीमा क्लेम प्रक्रिया आसान और तेज होगी, जिससे ग्राहकों को समय पर भुगतान मिलेगा और कंपनियों पर पारदर्शिता बनाए रखने का दबाव बढ़ेगा।

कल से शुरू फ्लिपकार्ट की 'GRWM GRWMÓ फैशन सेल मे मिलेगा

कंटेंट, कल्चर और फैशन का नया गरम गरम तड़का

नई दिल्ली ।

फ्लिपकार्ट फैशन ने अपने नए और ट्रेंडिंग कैंपेन '**GRWM GRWM**' के साथ फैशन शॉपिंग को एक नया अंदाज़ दिया है। लद्दठुं के बीच लोकप्रिय **"Get Read4 With** रूद्द÷ ट्रेंड को भारतीय ट्विस्ट देते हुए फ्लिपकार्ट ने इसे ÷गरम गरम÷ स्टाइल में पेश किया है, जहां फैशन सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि कंटेंट, कल्चर और ह्यद्द्यद्ध-**e&pression** का हिस्सा बनकर सामने आता है। 29 मई से 7 जून 2026 तक चलने वाली इस फैशन सेल में ग्राहकों को 10 लाख+ ट्रेंडी स्टाइल्स, 50 से ज्यादा इंटरनेशनल और होमग्रोन ब्रांड्स और कई आकर्षक ऑफर्स मिलेंगे। शुरुआती अनुमान बताते हैं कि सेल के दौरान 550 मिलियन+ विजिट्स आने की उम्मीद है, जिसमें लद्दठुं ग्राहकों की हिस्सेदारी लगभग 50ब्र तक हो सकती है। फ्लिपकार्ट फैशन इस कैंपेन के जरिए पारंपरिक **End of Season Sale** को एक नए, ट्रेंडिंग और कल्चर के हिसाब से बदलने की कोशिश कर रहा है। बैगी जींस, कोरियन ट्राउज़र्स, फ्लोरल ड्रेसेज़, पलाज़ो सेट्स और वायरल फैशन ट्रेंड्स के साथ यह सेल खासतौर पर युवा ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। सेल के दौरान **LeviÓs, Nike, Puma, Titan, Asics, Red Tape, Safari, Rare Rabbit ¥õÚU The Bear House** जैसे बड़े ब्रांड्स पर 90ब्र तक की छूट मिलेगी। साथ ही **Scratch Cards, SuperCoins** और बैंक ऑफर्स भी ग्राहकों के लिए उपलब्ध रहेंगे। फ्लिपकार्ट फैशन के वाइस प्रेसीडेंट कपिल थिरानी ने कहा, ÷आज फैशन की पसंद और नए स्टाइल्स की खोज पर खासकर युवा पीढ़ी के बीच क्रिएटर्स, ऑनलाइन समुदायों और डिजिटल संस्कृति का बड़ा प्रभाव है। '**GRWM GRWM**' के जरिए हम पारंपरिक सीज़न एंड सेल को नए रूप में पेश कर रहे हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि आज का युवा भारत फैशन को किस तरह देखता और अपनाता है। यह एक ताज़ा, ट्रेंड्स पर आधारित और आज की संस्कृति से जुड़ा खरीदारी अनुभव है। व्यक्तिगत पसंद के अनुसार सुझाव, आकर्षक फैशन डेस्टिनेशंस और बड़े व किफायती ब्रांड्स के चुने हुए विकल्पों के जरिए यह सेल देशभर के ग्राहकों तक नए फैशन ट्रेंड्स पहुंचा रही है। हम भारत के नए ग्राहकों के लिए फैशन को अधिक आसान, प्रासंगिक और सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और यह पहल उसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।÷

भारतीय एयरलाइंस ने घटाईं घरेलू उड़ानें, ईंधन महंगा, यात्री कम

एयर इंडिया, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 10 से 22 फीसदी तक सेवाओं में की कटौती

नई दिल्ली ।

भारत की प्रमुख विमानन कंपनियां, एयर इंडिया, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस, विमान ईंधन की बढ़ती कीमतों और अपेक्षा से कम यात्री मांग के कारण अपनी घरेलू उड़ानों में अस्थायी रूप से 10 से 22 प्रतिशत तक की कटौती कर रही हैं। यह फैसला पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से बढ़ी परिचालन लागतों और हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंधों के मद्देनजर लिया गया है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार एयर इंडिया जून और जुलाई के लिए अपनी घरेलू उड़ानों में 20-22 प्रतिशत की कटौती करेगी, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस जून के लिए अपनी घरेलू सेवाओं में 10 प्रतिशत की कमी कर रही है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए घरेलू उड़ानों में 12-15 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है। ये सभी कटौती ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम के तहत निर्धारित उड़ानों की तुलना में की गई हैं। एयर इंडिया प्रति सप्ताह लगभग 3,600 घरेलू उड़ानें संचालित करती है, जिसमें 22 फीसदी की कटौती से प्रति सप्ताह 790 से अधिक सेवाएं प्रभावित होंगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की लगभग 2,400 घरेलू उड़ानों में 10 फीसदी से कम का असर होगा। वहीं, इंडिगो, जो प्रति सप्ताह लगभग 13,000 घरेलू उड़ानें संचालित करती है, ने

मांग में कमी और वार्षिक मौसमी समायोजन को भी इस कटौती का कारण बताया है।

एयरलाइंस का यह कदम लागतों को नियंत्रित करने और मौजूदा बाजार परिस्थितियों के अनुकूल होने की रणनीति का हिस्सा है।

एशियाई शेयरों में गिरावट, वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स लुढ़का

नई दिल्ली।

ईरान पर यूएस के नए हमले के बाद गुरुवार को एशियाई शेयर गिरे। जबकि वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स सुबह के कारोबार में भारत के समय के अनुसार, 1 फीसदी तक गिर गए। नैस्डैक फ्यूचर्स 0.9 फीसदी नीचे थे। एसएंडपी 500 फ्यूचर्स 0.41 फीसदी गिरे और डाउ जोन्स फ्यूचर्स 0.21 फीसदी फिसले, जो बाद में यूएस मार्केट के लिए कमजोर शुरुआत का संकेत देते हैं। यूएस मिलिट्री ने ईरान के खिलाफ डिफेंसिव स्ट्राइक बताया, जिसके बाद एशियाई मार्केट में ज्यादातर गिरावट देखी गई। एक दिन पहले तेज़ी से गिरने के बाद तेल की कीमतें भी यूएसडी 1 प्रति बैरल से ज्यादा बढ़ गई। शुरुआती एशियाई ट्रेड में जापान का निक्केई 225 0.1 फीसदी से कम बढ़कर 65,039.78 पर आ गया, जबकि साउथ कोरिया का कोस्पी 1.2 फीसदी गिरकर 8,126.67 पर आ गया। हॉन्ग कॉन्ग का हैंग सेंग इंडेक्स 1.9 फीसदी गिरकर 24,855.86 पर आ गया, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.3 फीसदी गिरकर 4,080 पर आ गया।

भारत का ऊर्जा क्षेत्र रिकॉर्ड निवेश के लिए तैयार, 170 अरब पार होने की उम्मीद

वृद्धि मुख्य रूप से सौर ऊर्जा और तेल शोधन के तीव्र विस्तार के दम पर होगी

नई दिल्ली ।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऊर्जा क्षेत्र 2026 तक रिकॉर्ड 170 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का गवाह बनने वाला है। यह वृद्धि मुख्य रूप से सौर ऊर्जा और तेल शोधन के तीव्र विस्तार के दम पर होगी, क्योंकि देश बढ़ती ऊर्जा मांग व स्वच्छ ऊर्जा बदलाव के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। आईईए की विश्व ऊर्जा निवेश 2026 रिपोर्ट बताती है कि पिछले पांच वर्षों में भारत में ऊर्जा निवेश औसतन 11 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ा है। इस दौरान सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) में 25 प्रतिशत और तेल शोधन में 23 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। शोधन क्षेत्र में मजबूत निवेश से भारत 2030 तक अपनी क्षमता में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि करने की ओर अग्रसर है। हालांकि, 2020 के बाद से तेल और गैस के अपस्ट्रीम क्षेत्र में निवेश औसतन सात प्रतिशत प्रतिवर्ष घटा है। इसके विपरीत, भारत कोयला आपूर्ति में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है, जहां निवेश तीन गुना बढ़कर 2026 में 13 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ऊर्जा व्यय में लगभग आधी हिस्सेदारी बिजली क्षेत्र की है। सौर निवेश 20 अरब डॉलर तक पहुंचने के दम पर भारत ने 2025 का गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य पांच साल पहले ही हासिल कर लिया। अब जीवाश्म ईंधन पर हर एक डॉलर के मुकाबले नवीकरणीय ऊर्जा पर तीन डॉलर का निवेश हो रहा है। देश ग्रिड आधुनिकीकरण और बैटरी भंडारण पर भी खर्च बढ़ा रहा है।

होर्मुज व्यवधान के बीच तेल कंपनियों का मुनाफा सामान्य, अप्रत्याशित लाभ नहीं

लक्ष्य 2030 तक शोधन क्षमता को 31 करोड़ टन प्रति वर्ष से अधिक तक बढ़ाना

नई दिल्ली । सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 77,821 करोड़ रुपए का मुनाफा अर्जित किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह आंकड़ा संकट-प्रेरित अप्रत्याशित लाभ नहीं, बल्कि सामान्य लाभप्रदता की वापसी को दर्शाता है, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा और शोधन क्षमता के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है। विपक्षी दलों की आलोचना वित्त वर्ष 2024-25 के मुकाबले 130 फीसदी को लेकर रही है। हालांकि, वित्त वर्ष 2024-25 में लाभ घटकर 33,602 करोड़ रुपए हो गया था क्योंकि ओएमसी ने घरेलू एलपीजी कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए 40,434 करोड़ रुपए का घाटा उठाया था। इस एकमुश्त बोझ को समायोजित करने पर, मौजूदा लाभप्रदता वित्त वर्ष 2023-24 के 80,986 करोड़ रुपए के संयुक्त लाभ के करीब है। करीब 20 लाख करोड़ रुपये के संयुक्त कारोबार पर तीन से चार प्रतिशत का शुद्ध मुनाफा वैश्विक शोधन मानकों के अनुरूप है। उद्योग जगत के अधिकारियों का कहना है कि यह आय पूंजीगत व्यय, रिफाइनरी उन्नयन और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी है। लक्ष्य 2030 तक शोधन क्षमता को 31 करोड़ टन प्रति वर्ष से अधिक तक बढ़ाना है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की हालिया मूल्य वृद्धि का भी बचाव किया है, यह बताते हुए कि भारत में बढ़ोतरी पड़ोसी देशों से सीमित रही है।

नीति निर्माण को जमीनी रूप, वित्त मंत्रालय का राष्ट्रव्यापी उद्योग दौरा

डीईए के वरिष्ठ अधिकारी बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का भी दौरा करेंगे

नई दिल्ली ।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आर्थिक नीति निर्माण को सशक्त बनाने और पश्चिम एशिया संकट जैसी वैश्विक चुनौतियों के प्रबंधन हेतु उद्योग की जमीनी प्रतिक्रिया जानने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) इसके तहत देश भर में विनिर्माण इकाइयों और औद्योगिक समूहों का दौरा करेगा। यह पहल आर्थिक नीतियों को वास्तविक समय की जानकारी से जोड़ने और आगामी केंद्रीय बजट प्रस्तावों में साक्ष्य-आधारित नीतिनिर्माण को मजबूत करने पर केंद्रित है।

डीईए के वरिष्ठ अधिकारी सूक्ष्म, लघु एवं मझोली विनिर्माण इकाइयों के साथ-साथ बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का दौरा करेंगे। इन दौरों का उद्देश्य बुनियादी ढांचे, नियामकीय अड़चनों, आपूर्ति शृंखला में व्यवधान, वित्त तक पहुंच, कौशल की कमी और प्रौद्योगिकी अपनाने जैसी परिचालन एवं नीतिगत चुनौतियों पर प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना है।

सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में मजबूती के बावजूद, वैश्विक अनिश्चितता और पश्चिम एशिया संकट के चलते कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, रुपये में कमजोरी और आपूर्ति शृंखलाओं में बाधा जैसी समस्याओं ने निजी निवेश को असमान बना रखा है। इन समस्याओं की गहराई को समझने के लिए डीईए अधिकतम पांच सदस्यों के दल भेजेगा, जिनकी अगुवाई अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे।

ये दल विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में दो से तीन दिन का दौरा करेंगे, जिसमें कम से कम दो स्टार्टअप से बातचीत भी शामिल होगी। कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार दलों को विनिर्माण, बुनियादी ढांचा, रोजगार एवं अनुसंधान क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) को कंपनियों और अधिकारियों के बीच बातचीत को सुगम बनाने को कहा गया है।

इन दौरों से प्राप्त विस्तृत क्षेत्रवार रिपोर्ट 10 दिन के भीतर आर्थिक कार्य सचिव को सौंपी जाएंगी, ताकि नीति निर्माण और क्रियान्वयन में सुधार किया जा सके और जमीनी हकीकतों के अनुरूप लक्षित हस्तक्षेप सुनिश्चित हो सकें।

दिल्ली में बीएंडबी इकाई के लिए नया मसौदा जारी, आठ कमरों की अनुमति का प्रस्ताव

सुरक्षा और स्वच्छता मानकों पर विशेष जोर; 30 दिनों में मांगे गए सुझाव

नई दिल्ली ।

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में आवासीय संपत्तियों में बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) इकाइयों के संचालन के लिए एक नई मसौदा नीति जारी की है। इस नीति के तहत अब निजी घरों में अधिकतम आठ कमरों और 16 बिस्तरों तक की बीएंडबी इकाईयां संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय निवासियों के लिए आय के नए अवसर पैदा करना है।

दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा जारी मसौदा प्रस्ताव में बीएंडबी इकाइयों को दो मुख्य श्रेणियों- गोल्ड और सिल्वर में वर्गीकृत करने की बात कही गई है। इन इकाइयों का वर्गीकरण कमरे के आकार, उपलब्ध सुविधाओं, स्वच्छता और सुरक्षा मानकों के आधार पर किया जाएगा।

गोल्ड श्रेणी के लिए कमरों का न्यूनतम आकार 120 वर्ग फुट और बेहतर सुविधाएं अनिवार्य होंगी, जबकि सिल्वर श्रेणी में 100 वर्ग फुट के कमरे और बुनियादी सुविधाएं पर्याप्त मानी जाएंगी। मसौदा नीति में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सभी बीएंडबी इकाइयों के लिए अतिथि रजिस्टर का रखरखाव, पुलिस सत्यापन और विदेशी मेहमानों से संबंधित नियमों का पालन अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, आग बुझाने का उपकरण, प्राथमिक उपचार किट और आपातकालीन संपर्क विवरण रखना भी आवश्यक होगा। नीति में सीसीटीवी कैमरों को केवल प्रवेश द्वार और सामान्य क्षेत्रों तक सीमित रखने का भी प्रस्ताव है, ताकि मेहमानों की निजता सुनिश्चित की जा सके।

स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए, कमरों और साझा स्थानों की नियमित सफाई, कचरे का उचित पृथक्करण और पर्याप्त खुली हवा सुनिश्चित करनी होगी। परिसर में मालिक या एक केयरटेकर की उपलब्धता भी अनिवार्य रहेगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह नीति केवल आवासीय संपत्तियों पर लागू होगी और इन इकाइयों में रेस्टोरेंट, बार या किसी अन्य व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। इस कदम से पर्यटकों को किफायती और स्थानीय अनुभव वाले ठहराव का विकल्प मिलेगा, जिससे दिल्ली का पर्यटन क्षेत्र मजबूत होगा। इस मसौदा नीति पर हितधारकों और आम जनता से 30 दिनों के भीतर सुझाव मांगे गए हैं, जिसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

सीबीएसई मूल्यांकन विवादः छात्रों के हित में है ऑन-स्क्रीन मार्किंग, कमियों की जिम्मेदारी लेता हूँ

गड़बड़ी मिली तो होगी सख्त कार्रवाई, तकनीकी सुधार के लिए आईआईटी की मदद

राहुल गांधी के आरोपों पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार

नई दिल्ली ।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को आश्वासन दिया कि यदि इस प्रक्रिया में कोई जानबूझकर की गई लापरवाही या गड़बड़ी पाई जाती है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सीबीएसई ने लगभग चालीस करोड़ स्कैन किए गए पन्नों से जुड़ा एक बड़ा डिजिटल मूल्यांकन अभियान चलाया है।

परीक्षा में शामिल हुए सत्रह लाख छात्रों में से सीबीएसई ने करीब अठावन लाख उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखा है। प्रत्येक उत्तर पुस्तिका में लगभग चालीस पन्ने होते हैं, यानी कुल मिलाकर करीब चालीस करोड़ स्कैन किए गए पेज। पहली बार सीबीएसई ने ऑन-स्क्रीन मार्किंग के जरिए मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी की है। ओएसएम को एक प्रगतिशील और छात्र-हितैषी पहल बताते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दुनियाभर के कई विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान छात्रों के लिए पारदर्शिता और पहुंच में आसानी सुनिश्चित करने के लिए इसी तरह की प्रणालियां अपना रहे हैं। यह प्रणाली छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिकाएं देखने और अपने अंकों से जुड़े किसी भी संदेह को दूर करने में मदद करती है। ओएसएम को छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है, हालांकि, कुछ कमियां सामने आई हैं और वे उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी छात्र के सवालों का जवाब मिले बिना न रहे। प्रधान ने आगे बताया कि इस प्रणाली से जुड़े तकनीकी और परिचालन मुद्दों को हल करने के लिए आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास की मदद ली गई है। उन्होंने कहा कि आईआईटी के प्रोफेसरों के समूह इस मामले को देख रहे हैं।

यदि कोई जानबूझकर की गई गड़बड़ी पाई जाती है, तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।

इसके साथ ही, भुगतान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सीबीएसई पोर्टल को अब चार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक के पेमेंट गेटवे के साथ जोड़ दिया गया है। सीबीएसई परीक्षा प्रक्रिया में कथित विसंगतियों को लेकर राहुल गांधी की आलोचना का जवाब देते हुए प्रधान ने कांग्रेस नेता पर सरकार द्वारा शुरू की गई हर सुधार पहल का विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीबीएसई पहले ही अपना स्पष्टीकरण जारी कर चुका है और यह प्रक्रिया भारत सरकार की खरीद नीति के अनुसार पूरी की गई थी।

उन्होंने राजनीतिक पार्टियों से यह भी अपील की कि वे छात्रों से जुड़े मुद्दों का राजनीतिकरण न करें, क्योंकि छात्र पहले से ही तनाव में हैं और हमें उनके बीच और ज्यादा चिंता पैदा करने से बचना चाहिए। इससे पहले बुधवार को सीबीएसई ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उन आरोपों को खारिज कर दिया था, जिनमें बोर्ड की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली पर सवाल उठाए गए थे।

कर्नाटक में राजनीतिक उलटफेरः डीके अगले मुख्यमंत्री, समर्थक खुशी से झूमते दिखे

कर्नाटक।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के इस्तीफे की खबर सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। इस खबर के बाद उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के घर पर जश्न का माहौल बन गया है, जो राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बेंगलुरु के सदाशिवनगर स्थित उनके आवास के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई। समर्थक खुशी से झूमते, नारे लगाते और मिठाइयां बांटते दिखाई दिए। बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था। सूत्रों के अनुसार, सिद्दारमैया ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के सामने अपने इस्तीफे के फैसले की घोषणा की।

उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति, सरकारी गारंटी योजनाओं को लागू करने की चुनौतियों और भविष्य में कल्याणकारी कार्यक्रमों को जारी रखने की आवश्यकता पर बात की। बताया जाता है कि सिद्दारमैया ने मंत्रियों को सूचित किया कि कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें डीके को अगला मुख्यमंत्री बनाने का निर्देश दिया है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने इस घोषणा पर अपनी सहमति और समर्थन व्यक्त किया, जिसके बाद सिद्दारमैया ने उनसे सुशासन और कल्याणकारी कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना जारी रखने का आग्रह किया।

घोषणा करते समय सिद्दारमैया शांत और संयमित दिखे, लेकिन अपनी बात खत्म करने के बाद वे भावुक हो गए।

उन्होंने सहयोगियों से कहा कि वे अपने द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट हैं। उनके करीबी कई मंत्री, जिसमें श्रम मंत्री संतोष लाड भी शामिल थे, इस दौरान भावुक हो उठे। इस बीच, कैबिनेट बैठक के बाद डीके अपने आवास लौट आए। उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि वे नौनाविनकेरे मठ जाकर संत अज्जैया स्वामीजी का आशीर्वाद लेने और शपथ ग्रहण समारोह के लिए शुभ मुहूर्त पर चर्चा करने की उम्मीद कर रहे हैं। इस यात्रा में उनकी बेटी भी उनके साथ होंगी।

पद्मश्री डॉ. बशीर बद्र का निधन, 91 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

भोपाल ।

प्रसिद्ध उर्दू शायर, आधुनिक गजल के उस्ताद और पद्मश्री से सम्मानित डॉ. बशीर बद्र का लंबी बीमारी के बाद भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके इंतकाल से उर्दू शायरी के एक सुनहरे दौर का अंत हो गया है। डॉ. बद्र एक जमाने में मेरठ के साहित्यिक आयोजनों की शान हुआ करते थे। वे मेरठ कॉलेज के उर्दू विभाग में प्रोफेसर भी थे और छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय थे। उन्होंने देश-विदेश के मुशायरों में अपनी शायरी से खूब वाहवाही बटोरी। 80 के दशक तक वे देश के बड़े शायरों में शुमार हो चुके थे। लेकिन वर्ष 1987 के भीषण दंगों में जब दंगाइयों ने मेरठ स्थित उनके आवास विकास कॉलोनी के एमआईजी मकान को भी नहीं बख्शा, तब उन्होंने हमेशा के लिए अपने शहर मेरठ को छोड़ दिया। इसके बाद वे भोपाल आ गए और अपनी अंतिम सांस तक वहीं रहे। हालांकि, मेरठ हमेशा उनके दिल में बसा रहा, क्योंकि यह शहर उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा था। उनकी शायरी ने मोहब्बत, तन्हाई, इंतज़ार और ज़िंदगी के गहरे जख्मों को खूबसूरत शब्दों में पिरोया। उनकी भावनाएं और उनके शेर पीढ़ियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहने वाले है। अपने शहर मेरठ से रुखसत होते हुए, उन्होंने उसके बदलते मिज़ाज पर एक शेर कहा था जो काफी चर्चित हुआ और उनकी दूरदृष्टि को दर्शाता है।

स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत का डंकाः अमेरिका-चीन के क्लब में शामिल

लॉन्च हुआ पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक प्लेटफॉर्म 'मिशन साना'
स्वदेशी हाइड्रोजन बैलून तकनीक से दुनिया में बड़ा दबदबा
सस्ते इंटरनेट और सटीक आपदा प्रबंधन का नया दौर
-25 किमी ऊंचाई तक पहुंचा 'विस्टा'

नई दिल्ली ।

भारत ने अंतरिक्ष और नियर स्पेस तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। निजी अंतरिक्ष कंपनी रेड बैलून एरोस्पेस ने देश का पहला स्वदेशी सुपर-प्रेशर स्ट्रेटोस्फेरिक प्लेटफॉर्म 'मिशन साना' सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसके साथ ही भारत अमेरिका, फ्रांस, जापान और चीन जैसे चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है, जिनके पास स्वदेशी हाइड्रोजन स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून क्षमता मौजूद है। वर्ष 2025 में परिचालन शुरू करने वाली रेड बैलून एरोस्पेस ने महज आठ महीनों में अपनी पहली वाणिज्यिक उड़ान को अंजाम देकर तेजी से विकसित होने वाली वैश्विक परियोजनाओं में जगह बना ली है। कंपनी का 'विस्टा' सुपर-प्रेशर प्लेटफॉर्म विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी स्टेडियम से लॉन्च किया गया, जिसने पृथ्वी से करीब 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर कई तकनीकी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। इस मिशन में सात राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के पेलोड शामिल थे। इनमें जैविक प्रयोग प्रणाली, प्रणोदन तकनीक, ऑनबोर्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, पृथ्वी अवलोकन सेंसर और नेविगेशन सत्यापन प्रणाली जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का परीक्षण किया गया। सभी प्रयोग सफल रहने से अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मानकों के अनुरूप भारत की तकनीकी क्षमता साबित हुई है। 'मिशन साना' दूरसंचार, आपदा प्रबंधन, पृथ्वी अवलोकन और निगरानी के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है। विस्टा प्लेटफॉर्म ऊंचाई पर एक टावर की तरह काम करता है, जिससे उन इलाकों में भी नेटवर्क और निगरानी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जहां सामान्य संचार व्यवस्था कमजोर है। कंपनी के सह-संस्थापक और सीईओ सीथीएस किरण ने कहा कि विस्टा उनकी मुख्य प्लेटफॉर्म तकनीक है और आने वाले महीनों में इसकी क्षमताओं का और विस्तार किया जाएगा। वहीं, सीओओ सिरीश पल्लिकोंडा ने बताया कि एक ही मिशन के जरिए कई संगठनों और उद्योगों को सेवाएं देने से लागत कम होगी और नियर स्पेस तक पहुंच आसान बनेगी।

हाईकोर्ट की सख्ती टिप्पणी कहा- जज भ्रष्ट थे और हैं, इन्हे पवित्र न समझें

चेन्नई।

मद्रास हाईकोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार मौजूद है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भ्रष्ट जज पहले भी थे और आज भी हैं, इसलिए जजों के साथ ऐसा व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है जैसे वे पूरी तरह निष्कलंक या पवित्र हों। अदालत और न्यायाधीशों को आम आदमी की तार्किक आलोचना से ऊपर नहीं माना जा सकता। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन की पीठ ने यह टिप्पणियां ट्रायल कोर्ट के भ्रष्टाचार पर आधारित एक तमिल फिल्म पर प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए कीं। यह पूरा मामला तमिल फिल्म करुप्पु से

जुड़ा है, जिसके खिलाफ एक वकील ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की दलील थी कि फिल्म में अदालतों और पूरी कानूनी व्यवस्था का बेहद आपत्तिजनक और नकारात्मक चित्रण किया गया है, जो न्यायिक प्रणाली की छवि को बदनाम करता है। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि वह फिल्म में दिखाए गए अत्यधिक नकारात्मक चित्रण का पूरी तरह समर्थन नहीं करती, लेकिन न्यायपालिका की कमियों और सच से आंखें भी नहीं मूंद सकती। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की पीठ ने देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस.पी. भरूचा के उस ऐतिहासिक बयान का भी संदर्भ दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के लगभग 20 फीसदी जज भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मुद्दे पर वरिष्ठ वकीलों द्वारा समय-समय पर दिए गए बयानों का भी जिक्र किया।

इस्तीफा देकर सिद्धारमैया ने कहा.....मैंने वहीं किया जो आलाकमान द्वारा मुझसे कहा गया

बेंगलुरु ।

कर्नाटक के राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लगाकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया। बेंगलुरु में मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने आलाकमान के निर्देश का पालन करने की बात कही, मानो यह कहते हुए कि मैंने वहीं किया जो मुझसे कहा गया था। उन्होंने विश्वास जाहिर किया कि राज्यपाल संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनके इस्तीफे को स्वीकार करने वाले हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य में कांग्रेस के पास अब भी पूर्ण बहुमत है, और संविधान के अनुसार नई सरकार बनाने का अधिकार उनकी पार्टी को मिलना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर सोनिया, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उन्हें राज्य का नेतृत्व करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया था। अब पूरे राज्य की नजरें राजभवन और अगले मुख्यमंत्री के चेहरे पर टिक गई हैं। यह बड़ा सियासी कदम कर्नाटक कांग्रेस में लंबे समय से चल रहे सत्ता हस्तांतरण के विवाद का नतीजा है, जिस पर आखिरकार कांग्रेस हाईकमान ने निर्णायक मुहर लगी है। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में कई दौर की मैराथन बैठकों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिद्धारमैया पर मुख्यमंत्री पद छोड़ने का दबाव बनाया। दरअसल, 2023 की प्रचंड जीत के बाद डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ ढाई-ढाई साल के सत्ता साझेदारी फार्मूले पर सहमति बनी थी, और सिद्धारमैया पहले ही निर्धारित अवधि से अधिक समय तक मुख्यमंत्री रह चुके थे। बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया ने शुरुआत में जातीय जनगणना रिपोर्ट को कैबिनेट में पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन पार्टी नेतृत्व तत्काल नेतृत्व परिवर्तन के पक्ष में था। रिपोर्ट बताती है कि राहुल गांधी ने बंद कमरे में हुई बैठकों में सिद्धारमैया से कहा कि पार्टी की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पुराने वादे का सम्मान करना बेहद जरूरी है।

इन बैठकों में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी नेतृत्व परिवर्तन के पक्ष में बताए गए। राहुल गांधी ने दोनों नेताओं सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के साथ संयुक्त और अलग-अलग बैठकें कर पार्टी एकता बनाए रखने की अपील की। हालांकि, बैठक के दौरान सिद्धारमैया ने तर्क दिया था कि 2025 में पद छोड़ने को लेकर

कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ था, लेकिन राहुल गांधी अपने रुख पर अटल रहे। पार्टी नेतृत्व ने कहा कि सिद्धारमैया पहले ही आठ वर्षों से अधिक समय तक मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, इसलिए अब दूसरे नेताओं को मौका मिलना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक, बाद में सिद्धारमैया ने वरिष्ठ नेताओं केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला से भी चर्चा की, जिन्होंने उन्हें हाईकमान के निर्देश का पालन करने की सलाह दी।

मास्टरशेफ पंकज भदौरिया को ब्रेस्ट कैंसर, फैंस से मांगी दुआएं

मुंबई ।

देश की पहली मास्टरशेफ इंडिया विनर और सेलिब्रिटी शेफ पंकज भदौरिया इन दिनों एक कठिन दौर से गुजर रही हैं। हाल ही में उन्होंने अपने प्रशंसकों को बताया कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का पता चला है और वह इससे जूझ रही हैं। अस्पताल के बेड से तस्वीर साझा करते हुए, उन्होंने अपनी जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआओं और समर्थन की अपील की है। उनकी इस घोषणा के बाद से ही फैंस और सेलेब्स लगातार उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। 28 मई को पंकज भदौरिया ने एक भावुक पोस्ट साझा की थी। इसमें वह अस्पताल के गाउन में, मेडिकल वायर से जुड़ी हुई नजर आ रही थीं। उन्होंने लिखा, ÷मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है। मुझे आपकी दुआओं और सपोर्ट की जरूरत है।÷ इसके अतिरिक्त, उन्होंने मेडिकल टेस्ट करवाते हुए कुछ वीडियो भी शेयर किए, जिनमें उनके हाथ में कैनुला लगा दिखाई दे रहा था। एक वीडियो में उन्होंने लिखा था, ÷टेस्ट और ज्यादा टेस्ट के लिए जा रही हूं। यह कोई खुशी की जगह नहीं है।÷ एक अन्य वीडियो संदेश में पंकज ने खुद अपनी बीमारी के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा, ÷मैं आप सभी से यह बात खुद साझा करना चाहती थी क्योंकि आप लोग मेरे लिए परिवार जैसे हैं। इस समय मुझे आपकी दुआओं और सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है।÷ उन्होंने आगे जोड़ा, जैसा कहते हैं, दुआएं चमत्कार करती हैं, इसलिए मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। बता दें कि पंकज भदौरिया साल 2010 में 'मास्टरशेफ इंडिया' का पहला सीजन जीतकर पूरे देश में मशहूर हुई थीं और भारत की पहली मास्टरशेफ विनर बनी थीं। कुकिंग की दुनिया में आने से पहले, उन्होंने लगभग 16 साल तक एक इंग्लिश टीचर के रूप में काम किया था, जिसके बाद उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस रियलिटी शो में हिस्सा लिया।

बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शिकंजा, सीमा पर बढ़ी हलचल

कोलकाता ।

पश्चिम बंगाल में कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ने अब बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक रूप ले लिया है। राज्य में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान और उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई तेज होने के बाद भारत-बांग्लादेश सीमा पर हलचल बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद और सिलीगुड़ी के सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में लोग सीमा की ओर पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि राज्य प्रशासन ने सभी 23 जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने की प्रक्रिया शुरू की है, जहां संदिग्ध विदेशी नागरिकों को रखा जाएगा। इसके बाद उनकी नागरिकता की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी लगातार सख्त बयान दे रहे हैं और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल ने भी भारत-बांग्लादेश सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। वहीं बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा एजेंसी ने भी गश्त तेज कर दी है, जिससे सीमा क्षेत्रों में तनाव का माहौल देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कई संदिग्ध लोग लंबे समय से कोलकाता समेत अन्य शहरों में रहकर काम कर रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा अब बड़ा राजनीतिक विषय बनता जा रहा है।

हर्ष मल्होत्रा दिल्ली के नए भाजपा अध्यक्ष होंगे

हरियाणा, पंजाब और त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले

नई दिल्ली।

भाजपा ने संगठन में बड़े बदलाव शुरू कर दिए हैं। बीजेपी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत चार राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ ही पंजाब, हरियाणा और पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा की पार्टी इकाई को अब नए प्रदेश अध्यक्ष मिल गए हैं। हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली बीजेपी की कमान सौंपी गई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं। हर्ष मल्होत्रा केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल हैं और उनके पास सड़क परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री की जिम्मेदारी है। वह वीरेंद्र सचदेवा की जगह लेंगे। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब चुनावों में एक साल से भी कम समय बचा है और पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। पंजाब बीजेपी में अब सुनील जाखड़ की जगह केवल सिंह ढिल्लों नए अध्यक्ष होंगे। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष के पद पर केवल सिंह ढिल्लो की नियुक्ति को सिख बाहुल्य राज्य में सिख दांव के तौर पर देखा जा रहा है। केवल सिंह ढिल्लों कहावर सिख चेहरा हैं और कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं। सुनील जाखड़ के बाद अब केवल सिंह ढिल्लों बीजेपी की कमान संभालेंगे। बीजेपी ने त्रिपुरा में अभिषेक देबरॉय को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है ।

पूर्व सरपंच मां-बेटे सहित 4 लोगों की जिंदा जलाकर हत्या

स्कॉर्पियो में पीछे की सीट पर मिली तीन लाश, महिला की बॉडी खेत में पड़ी थी

अजमेर।

अजमेर में स्कॉर्पियो में पूर्व सरपंच मां-बेटे सहित 4 लोगों की जिंदा जलाकर हत्या कर दी। घटना शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर बोराड़ थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह 5:30 बजे की है। घटना श्रीरामपुरा गांव में हुई। इसमें पूर्व सरपंच रामसिंह चौधरी, उनकी मां और पूर्व सरपंच पूसी देवी, पत्नी सुरज्ञान देवी और भांजी महिमा की हत्या की गई। तीन शव गाड़ी में पीछे की तरफ थे। सुरज्ञान देवी की अधजली बॉडी खेत में पड़ी थी। सुरज्ञान देवी जिला परिषद मेंबर थीं। बताया जा रहा है कि परिवार कांग्रेस से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, पूसीदेवी के सीने में दर्द हो रहा था। इसलिए रामसिंह उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे। पहले हादसा में मौत बताई जा रही थी, लेकिन पुलिस झगड़े और हत्या की आशंका के एंगल से भी जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, पूर्व सरपंच रामसिंह चौधरी श्रीरामपुरा गांव के ही रहने वाले थे। घटना गांव से 1 किलोमीटर दूर हुई। पूर्व सरपंच की पत्नी और जिला परिषद सदस्य सुरज्ञान देवी के गले पर खून के निशान मिले हैं। वहीं, घर की जांच में पुलिस को 2 ईंटें और खून के निशान भी मिले हैं। घर पर माचिस भी मिली है, जिस पर खून के निशान है। पास ही ट्रैक्टर से डीजल निकालने की बात भी सामने आई। घर पूरी तरह धोया हुआ था। सवाल यह है कि अगर हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तो अराई की तरफ क्यों गए, जबकि बोराड़ा लेकर जाना था। लेकिन गाड़ी दूसरे रास्ते पर मिली है। जांच में गाड़ी की सीटें फोल्ड मिली हैं, अगर बैठते तो खुली हुई सीटें होतीं।

गंगा में 15 लोगों से भरी नाव डूबी

3 मौत, 4 लोग लापता

पटना।

पटना के बाढ़ में गंगा में नाव पलटने से 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। जबकि 4 लापता बताए जा रहे हैं। 7 लोगों को बचा लिया गया है। नाव पर करीब 14 लोग सवार थे। जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। हादसा बाढ़ के उमानाथ इलाके में हुआ है। मृतकों की पहचान नीलम कुमारी (30), श्रवण महतो (36) और काशी कुमार (15) के रूप में हुई है। श्रवण और काशी का संबंध पिता-बेटे का है। घायलों में राहुल कुमार, ममता देवी, कबूतरी कुमारी और 16 साल की एक नाबालिग लड़की शामिल है। बाकी 3 की पहचान अभी नहीं हो पाई है। नाव पर सवार सभी लोग बाढ़ थाना क्षेत्र के मासूमगंज बिंद टोली के निवासी थे।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्लन का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित।
(इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। RNI No. RAJHIN/2001/05699 मो. नं. 9928078717